

शोक-आश्वासन

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्मशाला के राजकीय महाविद्यालय की एक छात्रा की दुखद मौत पर शोक जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल देर शाम खेल व युवा सेवाएं मंत्री यादविन्द्र गोमा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री की परिजनों से फोन पर बात करवाई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच पूरी गंभीरता और तय समय में पूरी की जाएगी।

शिवराज-जी राम जी

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण-जी राम जी क़ानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी क़ानून श्रमिकों के हित में है क्योंकि इसमें बढ़े हुए भुगतान, बेरोजगारी भत्ते, विलम्बित भुगतान पर ब्याज और सौ की तुलना में सवा सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि इनसे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे गांवों में सार्थक योगदान भी दे सकेंगे।

वीबी-जी राम जी

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ना, जवाबदेही को सुदृढ़ करना और आय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जनजातीय जिला किन्नौर की योजना की लाभार्थी प्रोमिला ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के वीबी-जी राम जी में बदलने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रोजगार मिल रहा है। योजना के तहत एक सौ 25 कार्य दिवस तय किए गए हैं इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आर्थिकी में सुधार होगा।

मैं प्रोमिला नेगी केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा जी राम जी को मजबूत किये जाने के फ़ैसले का स्वागत करती हूँ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भी धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने जी राम जी के तहत के काम के दिनों को बढ़कार 125 दिन कर एक सराहनीय कदम उठाया है। किन्नौर जैसे दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में जी राम जी से लोगों को अपने गांव में ही काम मिलेगा।

चुनाव आयोग— ऐप

चुनाव आयोग ने ई.सी.आई—नेट ऐप में सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस ऐप पर लोग अपने जवाब 10 जनवरी तक दे सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं को बेहतर सेवाएं और चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए ये डिजिटल मंच बनाया है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐप का परीक्षण संस्करण बेहतर मतदाता सेवाएं, मतदान प्रतिशत रुझानों की त्वरित उपलब्धता और मतदान समाप्त होने के 72 घंटों के भीतर सूचकांक कार्डों का प्रकाशन करता है। इस ऐप का हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आयोग ने कहा कि लोगों से प्राप्त सुझावों की जांच की जाएगी और उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा।

सिंचाई योजना

जनजातीय जिला किन्नौर में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों और बागवानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत किन्नौर जिले के 55 किसानों और बागवानों को सिंचाई सुविधाओं के लिए 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया है। योजना के तहत किसानों को आधुनिक सिंचाई उपकरण उपलब्ध हुए हैं, जिससे पानी की बचत के साथ-साथ फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में भी सुधार होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर संवाददता की ये रिपोर्ट....

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले में टपक सिंचाई और फवारा सिंचाई जैसी आधुनिक जल-संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो सके। योजना के अंतर्गत किन्नौर जिले के 55 किसानों और बागवानों को सिंचाई सुविधाओं के लिए 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया है। इन लाभार्थियों को कुल 15 लाख 13 हजार 7 सौ 36 रुपये की सहायता राशि वितरित की गई है। टपक और फवारा सिंचाई प्रणाली से सेब, मटर, आलू और अन्य नकदी फसलों की खेती में बेहतर परिणाम मिलेंगे। साथ ही, पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से सुमेश नेगी।